जंग का एलान

हमास और आम फलस्तीनी आबादी का फर्क कहीं मिट न जाए। यही वजह है कि पीएम मोदी के ट्वीट के जरिए आतंकवाद के सवाल पर इस्राइल को पूरा समर्थन देने के बाद जब विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया जताई तो उसमें एक स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीन बनाने की दिशा में बातचीत की भी जरूरत बताई गई।

अनुज सनवाल।।

हमास के आतंकी हमले के बाद इस्राइल ने बाकायदा जंग का एलान कर दिया है और गाजा पर जल, थल, वायु– तीनों रास्तों से भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि, जवाबी कार्रवाई तो उसने हमले के दिन से ही शुरू कर दी थी। इस बीच अंतरराष्ट्रीय हलकों में इस्राइली हमले के संभावित नतीजों को लेकर चिंता की लकीरें गहरी होती दिखने लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने हमास और इस्राइल दोनों के नाम अपीलें जारी की हैं। उन्होंने हमास से कहा है कि वह सभी बंधकों को फौरन बिना शर्त रिहा कर दे और इस्राइल से अनुरोध किया है कि वह गाजा पट्टी तक मानवीय सहायता की अबाधित पहुंच सुनिश्चित करे। उनकी अपीलों का कितना असर होता है, यह देखना बाकी है लेकिन सबकी असल चिंता इस्राइल की संभावित कार्रवाई को लेकर है। ध्यान रहे, आतंकी हमला होने के बाद लगभग पूरी दुनिया ने हमास के कृत्य की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में एक स्वर से इस्राइल को समर्थन दिया था। लेकिन इस्राइल जिस तरह के कदमों की तैयारी कर रहा है, उसमें आशंका है कि हमास और आम फलस्तीनी आबादी का फर्क कहीं मिट न जाए। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट के जरिए आतंकवाद के सवाल पर इस्राइल को पूरा समर्थन देने के बाद जब विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया जताई तो उसमें एक स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीन बनाने की दिशा में बातचीत की भी जरूरत बताई गई।

यही नहीं आतंकी हमले के बाद से ही इस्राइल की जवाबी कार्रवाई को उसका अधिकार बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के स्वर भी कुछ बदले दिख रहे हैं। उन्होंने जहां यह भरोसा जताया है कि इस्राइल युद्ध संबंधी नियमों का पालन करेगा वहीं यह चेतावनी भी दी है कि गाजा पर इस्राइल का दोबारा कब्जा हुआ तो वह बड़ी भूल होगी। साफ है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की ओर से परोक्ष तौर पर ही सही लेकिन इस्राइल के लिए लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है। यह जरूरी इसलिए भी है कि कार्रवाई एक बार शुरू हो गई तो वह कितना लंबा चलेगी और उसमें किसका कितना नुकसान होगा इस बारे में अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इससे भी बड़ी बात यह कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सबसे बड़ा डर है कि इसका असर अन्य क्षेत्रों में न फैले। फिलहाल अमेरिका समेत तमाम ताकतें कोशिश कर रही हैं कि इसमें किसी और प्लेयर की एंट्री न हो। लेकिन आम फलस्तीनियों के जान–माल का बड़ा नुकसान पूरे खाड़ी क्षेत्र के लोगों को उद्वेलित कर सकता है जिसके बाद हालात को काबू में रखना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। बहरहाल, अभी तो सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि इस्राइली नेतृत्व इस कठिन समय में कितनी समझदारी दिखाता है। उम्मीद की जाए कि वह दुनिया के सामूहिक विवेक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा।

सिंहासन

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

यमराज की सभा और उनके सिंहासन का वर्णन भी किया गया है जिसे गरुनपुरान मे विष्णु जी इसे यमराज का मंदिर भी कहते है । इस मंदिर मे शंखो की ध्वनि लिए ठंडी हवा बहती है इस मंदिर मे घंटे और नागारों की ध्वनि हमेशा गूँजती रहती है। 500 योजन मे हजारो खंभो के ऊपर बना यह भावव्य महल साथ ही साथ लगातार बजने वाली ध्वनिया इस महल को संगीतमय बनती है। यहा पर अलग अलग प्रकार के पुस्प (फूल) हजारो की मटर्रा मे लगे है जो पूरे भवन खुशबूदार रखती है। शीतल और गर्म यहाँ दोनो प्रकार जल प्रवाहित होते रहते है। 10 योजन के नीले बादलो के समान एक सिंहासन पर स्वयम धर्मराज विराजमान होते है उनके मस्तक पर बेहद आकर्सक मुकुट सजा रेहता है और यमराज के चारों ओर अपसराए तथा गंधर्व उनकी सेवा मे लगी रहती है।

संपादकीय

ताकत या कमजोरी

जाहिर तौर पर मोदी सरकार की पहल ने विपक्षी खेमों का गणित खराब कर दिया है। धर्म और जाति के इस मिले–जुले समीकरण को काटने के लिए विपक्ष अब कास्ट सर्वे का ऐसा मुद्दा लाया है, जो ओबीसी वोटरों तक उसकी सीधी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन सवाल है कि जो पार्टियां एक परिवार और एक जाति में फंस गई हैं क्या वे सारी ओबीसी जातियों में पैठ बना पाएंगी? क्या ये पार्टियां टिकट बंटवारे के दौरान ओबीसी की सारी जातियों और ओबीसी महिलाओं को तरजीह दे पाएंगी? इसका जवाब अगले चुनावों के दौरान ही मिलेगा। बीजेपी का यह कार्ड ऐसा चला कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव ही नहीं, तमाम विधानसभा चुनावों में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को सवर्णों का 61 फीसदी, व्ठब का 58 फीसदी, आदिवासियों का 49 फीसदी, दलितों का 41 फीसदी और मुस्लिमों का 10 फीसदी वोट मिला था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद व्ठब नेताओं को सरकार, संगठन में भी अहमियत दी जा रही है। कास्ट सर्वे के असर की सीमाएं भी उसी से स्पष्ट होगी।

जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तभी से वह राजनीति को जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की वजह से उसकी लगातार हार हो रही है।

ओबीसी फैक्टर

धर्मेन्द्र कुमार सिंह।।

आम चुनाव अगले साल की शुरुआत में हैं, लेकिन उससे पहले पांच राज्यों द्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम– के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। नवंबर में होने जा रहे इन चुनावों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। लगता है कि आजादी के बाद पहली बार यह चुनावी जंग लगभग पूरी तरह जाति पर केंद्रित होगी।

इंडिया गठबंधन ने जाति की राजनीति पर बड़ा दांव खेला है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने आर्थिक–सामाजिक सर्वे और जाति जनगणना कराकर भी उसके आंकड़े ठंडे बस्ते में डाल रखा है। जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63 फीसदी है जिसमें 27.12 फीसदी पिछड़ा वर्ग और 36.01 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग है। दलितों की संख्या 19.65 फीसदी, सामान्य वर्ग 15.52 फीसदी और आदिवासी 1.68 फीसदी हैं। इस जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस रिपोर्ट से गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और अब केंद्र सरकार को यह काम देशभर में करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी ओबीसी की

मीटिंग के बाद देशव्यापी कास्ट सर्वे कराने की मांग रखी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कहा है कि विकास विरोधी लोग आज भी जात–पात के नाम पर देश को बांट रहे हैं। दूसरी ओर, राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक का नारा दिया है। गौर करने की बात है कि जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तभी से वह राजनीति को जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की वजह से उसकी लगातार हार हो रही है। यही वजह है कि जातीय जनगणना कराने के साथ ही महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा का प्रावधान जोड़ने की मांग उसने की है। सच है कि बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति के जरिये पिछड़ी जातियों को काफी हद तक साध लिया है। वहीं, विपक्षी पार्टियां ठश्रच के वर्चस्व को तोड़ने के लिए 34 साल पुराने मंडल हथियार का नए सिरे से सहारा ले रही हैं। हालांकि इसे लेकर इंडिया गठबंधन की अपनी परेशानियां भी हैं। इसकी बेंगलुरु की बैठक में देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठी थी, लेकिन मुंबई बैठक में इस पर मतभेद उभरे तो इसे राजनीतिक प्रस्ताव से हटा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तय किया गया कि इस पर समन्वय समिति सभी सहयोगी दलों से बातचीत करके रास्ता निकालेगी। 2011 की यूपीए सरकार के दौरान जाति और सामाजिक–आर्थिक सर्वे हुआ था, लेकिन उसे तकनीकी कारण बताकर सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्नाटक में भी सिद्दारमैया सरकार अपने पिछले कार्यकाल में ही जातीय जनगणना करवा चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। विपक्ष की मांग है कि 2011 के सर्वे को प्रकाशित किया जाए या फिर से पूरे देश में जाति जनगणना की जाए। मकसद है जाति के आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग उठाई जाए। राहुल गांधी ने इसी रणनीति के तहत संसद में महिला बिल पर बहस के दौरान केंद्र के विभिन्न विभागों के कुल 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी होने का मुद्दा उठाकर माहौल गरम कर दिया।

अष्टयोग-4904

6	1	4		2		
5	35	3	27	1	28	7
7		5			6	
	31		37	7	34	
	3	6		5	2	4
2	27		41	4	29	
4		7		6		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4903 का हल

4	1	5	6	2	7	3
6	35	6	30	1	32	7
7	5	1	3	6	4	2
1	29	2	31	4	31	5
2	4	7	5	3	6	1
3	29	4	40	5	34	6
5	1	3	6	7	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

हिंदुत्व की राजनीति में ओबीसी की खास जगह

मोहन। ध्यान रहे, 2014 के पहले बीजेपी को लोकसभा में कभी बहुमत नहीं मिला था। सत्ता की चाहत में उसने बड़ा कार्ड खेला। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ताकत उनकी हिंदुत्व समर्थक छवि थी, लेकिन यह तथ्य भी अपनी जगह था ही कि वह ओबीसी समुदाय के हैं। इसके जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी आंकड़ों की झड़ी लगा दी। मोदी कैबिनेट में 29 मंत्री ओबीसी समूह से आते हैं। बीजेपी के 29 फीसदी यानी 85 सांसद ओबीसी हैं। पार्टी के कुल 1358 विधायकों में से 365 यानी 27 फीसदी ओबीसी के हैं। उसके 163 एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य हैं जिनमें 65 ओबीसी हैं। उनकी बातों का मतलब यह था कि हिंदुत्व की राजनीति में ओबीसी की खास जगह है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे से हटने को तैयार नहीं। उसकी रणनीति इसी से समझी जा सकती है कि ठश्रच के तमाम पैंतरों के जवाब में वह एक से एक नए मुद्दे उठाकर राजनीति को जाति की पटरी पर लाने का प्रयास जारी रखे हुए है।